कोई सफाई नहीं

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक न्याय) से संबंधित है।

द हिन्दू

02 अक्टूबर, 2021

परिवर्तनशील शहरी भारत के लिए समुदाय-आधारित कदमों को एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की आवश्यकता है।

अपनी सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करने के सात साल बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू)' और 'अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत)' के दूसरे चरण की घोषणा की है, जिसमें भारत के शहरों को साफ बनाने का एक नया वादा है।

महात्मा गांधी ने जिस वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और पूर्ण स्वच्छता पर एक सदी पहले भी जोर दिया था, वह सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज भी काफी हद तक आकांक्षी बना हुआ है। प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल का हालिया बयान यह स्पष्ट करता है कि गंदे, बेतरतीब शहरों का होना गंदगी को घर ले जाता है।

शहरी भारत, उनके विचार में, वियतनाम के उन शहरों की बराबरी करने में असमर्थ है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय तुलनीय है, स्वच्छ भारत कार्यक्रम को जबरदस्त समर्थन मिलने के बावजूद शहरी प्रबंधन क्षमताओं में एक बड़ी कमी है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, ₹1.41 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ, अमृत मिशन द्वारा कवर नहीं किए गए स्थानों में कचरा मुक्त शहरों और शहरी हरे और काले पानी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

अपने पहले चरण में, मिशन पर ₹3,532 करोड़ का बकाया था, क्योंकि कुल आवंटन ₹14,622 करोड़ था जबकि संचयी रिलीज ₹11,090 करोड़ थी। क्षमता और शासन का मुद्दा चुनौती को रेखांकित करता है। उत्पन्न 1.4 लाख टन के मुकाबले प्रति दिन केवल एक लाख टन ठोस कचरे को संसाधित करने में सक्षम होने के लिए - एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए जो ठोस और तरल अपशिष्ट को संसाधन के रूप में मानता है।

संसाधन वसूली में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, जिसके लिए नगरपालिका, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को नियंत्रित करने वाले नियम प्रदान करते हैं, एक साझेदारी की माँग करते हैं जो घरों को एक ठोस प्रोत्साहन देता है। बड़े निगमों को मेगा अनुबंध जारी करने का वर्तमान मॉडल - उदाहरण के लिए विकेन्द्रीकृत समुदाय-स्तर के संचालन के विपरीत - स्रोत पर कचरे के अलगाव को एक गैर-स्टार्टर छोड़ दिया है।

संचालन के विस्तार के अभाव में, जो बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कर सकता है, और सामग्री वसूली के लिए मिलान सुविधाओं का निर्माण, एसबीएम-यू 2.0 बढ़ती अर्थव्यवस्था में कचरे की बढ़ती मात्रा के साथ तालमेल नहीं रख सकता है।

स्वच्छता पर, घरेलू, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के लिए लक्ष्यों को पार करने का प्रभावशाली दावा भले ही सरकार करती हो लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे पता चला है कि पानी के कनेक्शन के बिना उनमें से कई शौचालय अनुपयोगी हैं और जर्जर हो गए हैं।

राज्य सरकारें और नगरपालिका, जो कचरे और स्वच्छता के मुद्दों पर भारी उठापटक करती हैं, को सिस्टम के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। जैसा कि चीजें खड़ी हैं, यह शहरी भारत के लिए खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ +) की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक लम्बा रास्ता तय करना है। क्योंकि इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुले में शौच का कोई दर्ज मामला नहीं होना चाहिए और सभी सार्वजनिक शौचालयों को बेहतर स्थिति में बनाए रखने और कार्य करने की आवश्यकता है।

समान रूप से, लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% नल के पानी की आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्राप्त करने की उच्च महत्वाकांक्षा लाखों लोगों के लिए कम से कम अच्छे सार्वजनिक किराये के आवास को सुलभ बनाने पर निर्भर करती है।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

अमृत 2.0 मिशन

- अमृत 2.0 मिशन से शहरों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, यह शहरों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह मिशन 4,700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 500 अमृत शहरों में 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और सीवरेज की 100% कवरेज प्रदान करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इस मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू)

- SBM-U 2.0 मिशन सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाना चाहता है।
- यह मिशन 3R के सिद्धांतों का उपयोग करके ठोस कचरे के स्रोत पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करेगा। SBM-U 2-0 के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. अमृत 2.0 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह मिशन 4,700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
2. इस मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2

(c) 1 एवं 2 दोनो **(d)** न तो 1 न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements about AMRUT 2.0 Mission-

1. This mission has been launched with an objective to provide 100% coverage of water supply to all households of 4,700 urban local bodies.
2. An outlay of Rs 2.87 lakh crore has been approved for this mission.

Which of the above statement is/are true-

(a) Only 1 **(b)** Only 2

(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "भारत मे स्वच्छता की कमी केवल नीतिगत समस्या ही नही अपितु जनता के स्तर पर व्याप्त अभिवृत्तिक समस्या भी है, अतः दोनो स्तरों पर बदलाव करने की आवश्यकता है।" टिप्पणी करें। (250 शब्द)

Q. "The lack of cleanliness in India is not only a policy problem but also an attitude problem prevailing at the level of the people, so there is a need to make changes at both the levels." make a comment. (250 Words)

GS World
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।